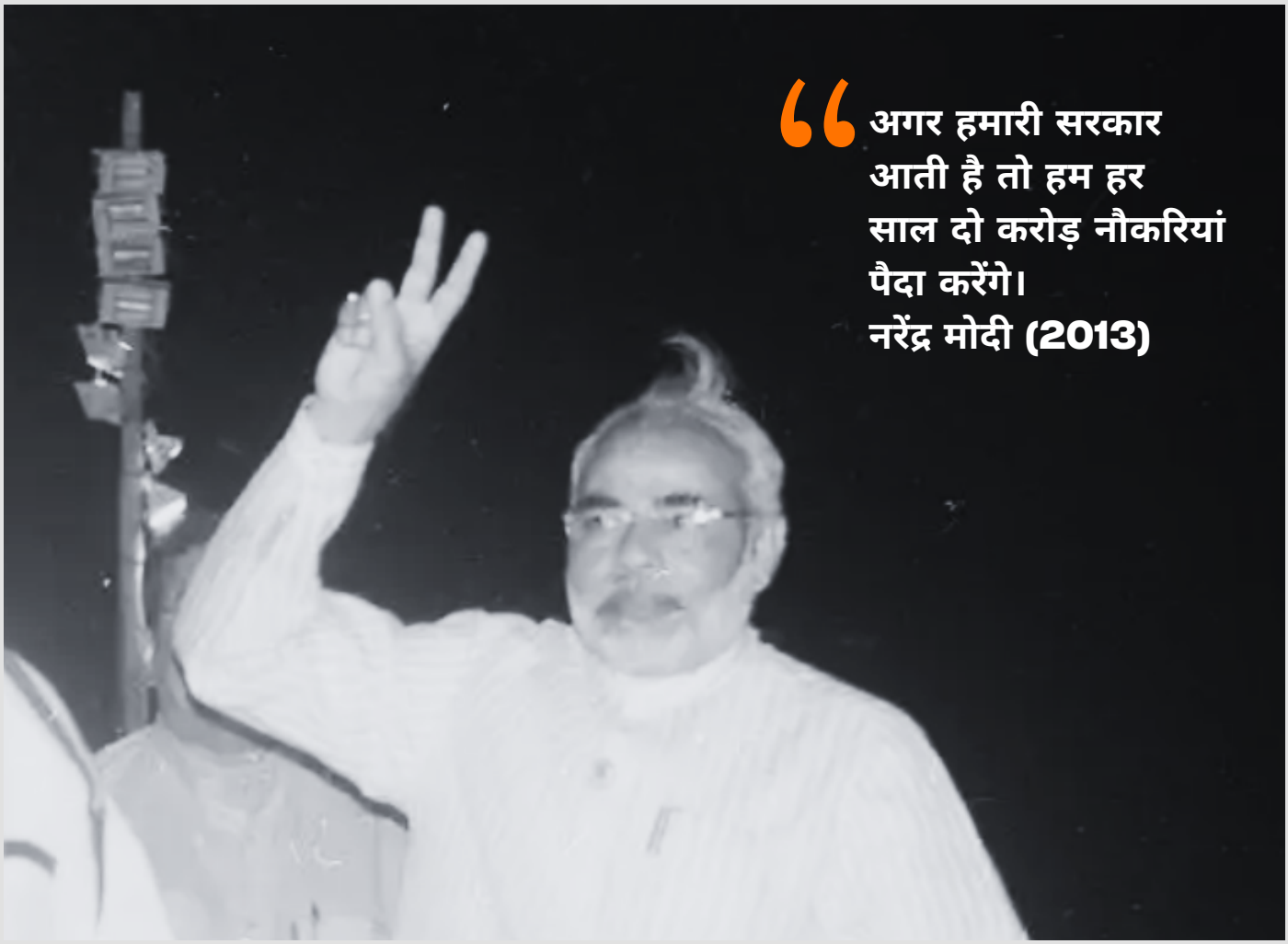

रोज़गार, वेतन और गैर-बराबरी

11 मार्च 2024

यहां प्रस्तुत किए गए सभी आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सरकारी आंकड़ों से लिए गए हैं। हमने यहां आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस/PLFS) और अब बंद कर दिए गए रोज़गार-बेरोज़गारी सर्वेक्षण से लिए गए आंकड़ों का इस्तेमाल किया है। यह विश्लेषण वर्ष 2022-23 में देश के 49 करोड़ मज़दूरों की स्थिति की तस्वीर पेश करता है।

TEN YEARS OF NDA • A GUARANTEE CHECK •

दावे

नरेंद्र मोदी के वादे

2

करोड़ नौकरियां
हर साल

“रोज़गार और स्वरोज़गार के मौके
सभी को एक समान रूप से
उपलब्ध कराए जा रहे हैं”

प्रधानमंत्री मोदी (2022)

“भारत के विकास की दिशा
और गति सभी क्षेत्रों में नए
रोज़गार का निर्माण कर रही है”

प्रधानमंत्री मोदी (2023)

सच्चाई

खुद सरकार के आंकड़े क्या बताते हैं?

तालिका 1*	स्वरोज़गार		अनियमित रोज़गार		नियमित वेतन रोज़गार	
वर्ष	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
2011-2012	51.5%	56.5%	28.2%	28.7%	20.3%	14.8%
2022-2023	53.4%	64.3%	22.8%	17.1%	23.8%	18.6%

वर्ष 2011-12 से 2022-23 के दौरान, कुल रोज़गार में स्वरोज़गार का अनुपात बढ़ा है। आधे से अधिक पुरुष और दो-तिहाई से अधिक महिलाएं '**स्व-रोज़गार**' पर निर्भर हैं; इस श्रेणी में ग्रामीण बुनकर, किसान, कुम्हार, शहर में रेडी लगाने वाले, दरजी, नाई, इत्यादि और लघु घरेलू उद्योग में बिना वेतन काम करने वाले मज़दूर भी शामिल हैं।

स्वरोज़गार सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन सच्चाई यह है कि अच्छे वेतन और सामाजिक सुरक्षा वाली नौकरियों की कमी की वजह से लोगों के पास **कम-वेतन वाले स्वरोज़गार** के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। भूख और मौत से बचने के लिए के लिए मजबूरी में कई लोगों को स्वरोज़गार सहारा लेना पड़ रहा है।

घरेलू आमदनी में बढ़ोत्तरी न होने की वजह से गरीब घरों की महिलाओं को अपने खेत पर या दुकान में बिना किसी वेतन के काम करने पर मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें वेतन वाला कोई और रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। पिछले 5 सालों में, बिना वेतन के घरेलू स्तर पर काम करने वाली महिलाओं का अनुपात **4 में से 1** से बढ़कर **3 में से** 1 हो गया है।

सिर्फ केंद्रीय सरकार के ही **9.79 लाख पद खाली** पड़े हैं। इन आंकड़ों का खुलासा दिसंबर 2022 में खुद राज्य मंत्री, जीतेन्द्र सिंह ने लोक सभा में किया था। नियमित वेतन वाले रोज़गार का अनुपात परुषों के लिए 3 प्रतिशत अंको से बढ़ा है और महिलाओं के लिए 3.8 प्रतिशत अंकों से।

*वर्ष 2011-12 के आंकड़े नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस/NSS) के सर्वेक्षण से हैं। इस सर्वेक्षण को अब बंद कर दिया गया है और 2017-18 से केंद्र सरकार ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस/PLFS) की शुरुआत की है।

“युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है”

सच्चाई

युवाओं में रोज़गार की हकीकत क्या है?

रेखाचित्र 1* में उम्र और शिक्षा के स्तर के अनुसार बेरोज़गारी दर दिखाई गई है।

25

साल की उम्र के स्नातकों (ग्रेजुएट) में से

42%

बेरोज़गार हैं!

रेखाचित्र 1: उम्र और शिक्षा के स्तर के अनुसार बेरोज़गारी दर*

	25 से कम	25-29	30-34	35-39	40+
स्नातक और उससे ऊपर	41.7	21.4	7.9	3.4	1.4
उच्च माध्यमिक	16.4	6.3	4.1	1.4	1.1
माध्यमिक	12.2	6.3	4.1	1.4	1.1
प्राथमिक या पूर्व-माध्यमिक	10.2	3.4	2.4	1.6	1.6
शिक्षित लेकिन प्राथमिक से कम	8.9	0.3	2.8	1.9	2.3
अशिक्षित	7.2	2.4	2.6	0.9	2.1

*स्रोत: पीएलएफएस (PLFS) 2022-23

दावे

“यह वो समय है जब अवसर और आमदनी दोनों बढ़ रहे हैं और गरीबी घट रही है।”

प्रधानमंत्री मोदी, फ़रवरी 2024

“बढ़ती खुशाली देश की प्रगति के लिए अच्छा संकेत है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम आर्थिक खुशहाली के एक नए दौर की ओर अग्रसर हैं और 2047 तक ‘विकसित भारत’ के अपने सपने को पूरा कर लेंगे”

प्रधानमंत्री मोदी, अगस्त 2024

“हमारी सरकार के दौरान राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन में 42% की बढ़ोत्तरी की गई। हम अगले पांच सालों में भी यही दिशा बनाए रखेंगे ताकि सभी मज़दूरों को सम्मानजनक जीवन हासिल हो सके।”

भाजपा का घोषणापत्र (2019)

सच्चाई

वेतन और कमाई

विभिन्न श्रेणियों के रोज़गार के लिए

रेखाचित्र 2: नियमित वेतन और अनियमित रोज़गार की श्रेणी के मज़दूरों के लिए औसत साप्ताहिक वेतन (महंगाई दर घटाने के बाद)

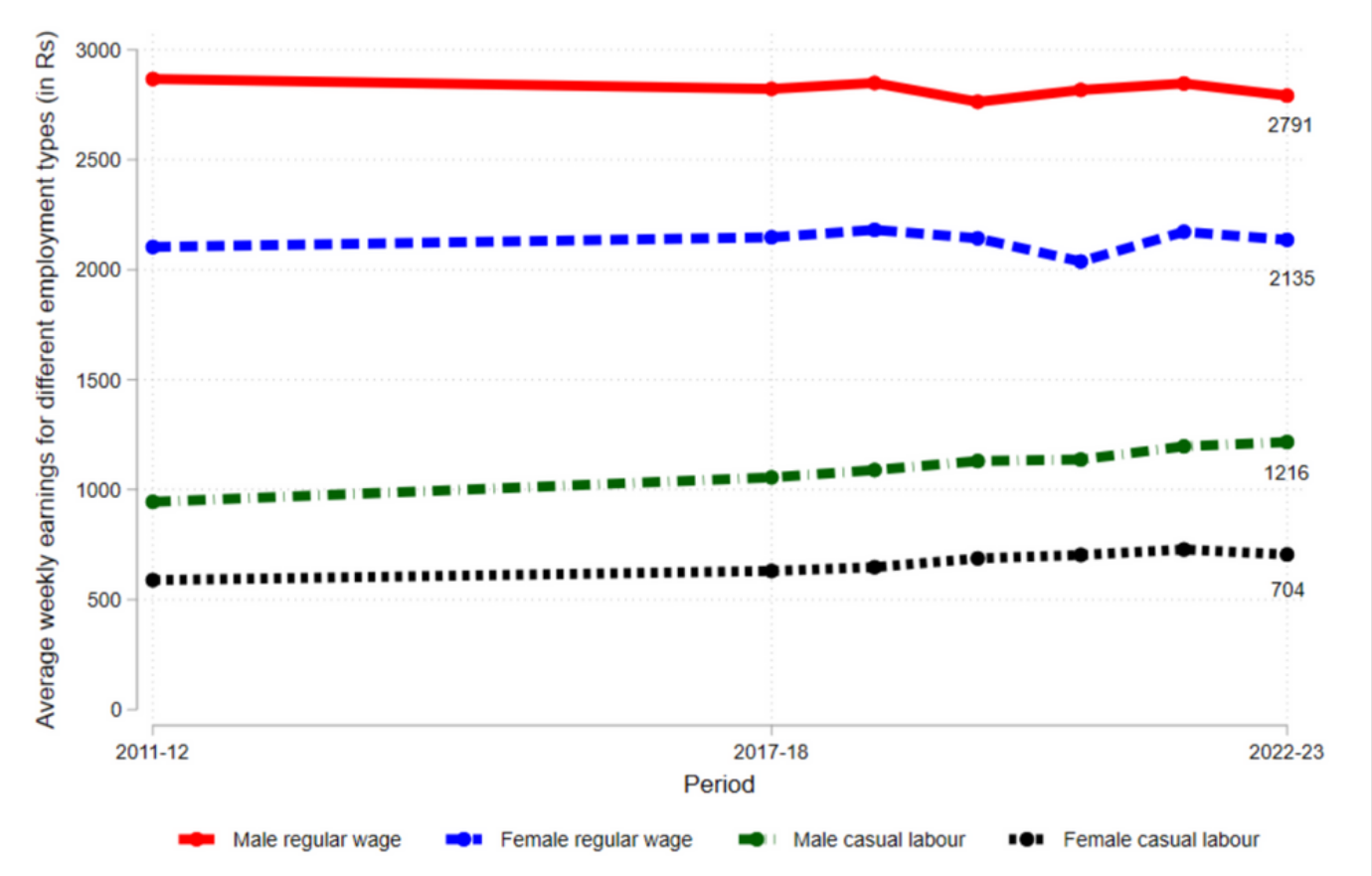

रेखाचित्र 2 और 3 दर्शाते हैं कि वास्तविक वेतन का स्तर, यानी महंगाई घटाने के बाद वेतन का स्तर ज्यों का त्यों रहा है। 100 रुपए से 2011 में जितने मूल्य का सामान खरीदा जा सकता था, महंगाई की वजह से उतना सामान 2024 में नहीं खरीदा जा सकता है।

महंगाई की दर को घटाकर हम दो अलग-अलग समय के वेतन की तुलना कर सकते हैं। अगर हम 2011 के मुकाबले आज ज़्यादा कमा रहे हैं तो रेखाचित्र 2 और 3 में दिखाई गए रेखाएं ऊपर जानी चाहिए, लेकिन चित्र में यह रेखाएं सपाट हैं जिसका मतलब हुआ कि वास्तविक वेतन में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।

यही नहीं, कई अनियमित मज़दूरों को रोज़ काम नहीं मिलता है जो उनकी आर्थिक स्थति को और नाज़ुक बनाता है।

सच्चाई

रेखाचित्र 3: स्वरोज़गार की श्रेणी के मज़दूरों के लिए औसत साप्ताहिक वेतन (महंगाई दर घटाने के बाद)

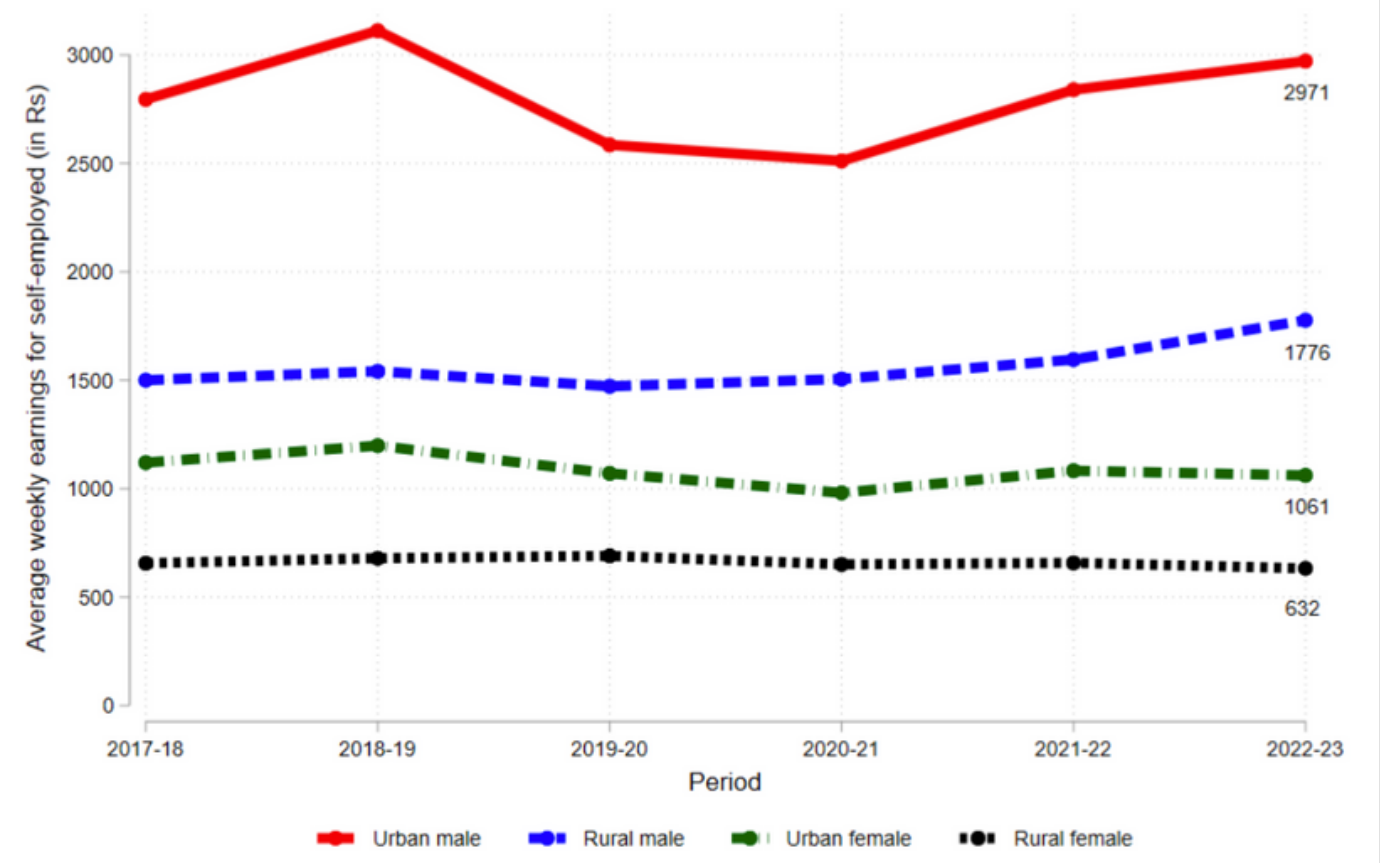

भारत सरकार के श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा 2019 में वेतन के मूड पर गठित की गई अनूप सतपथी की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने कहा था कि राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन **कम से कम 375 रुपए होना चाहिए।**

इसे एक औसत व्यक्ति के लिए संतुलित भोजन पर होने वाले खर्च के आधार पर तय किया गया था। न्यूनतम वेतन के अलावा, इस समिति ने शहरी मज़दूरों के लिए आवासीय भत्ते के तौर पर महीने में अतिरिक्त 1,430 रुपए की सिफारिश भी की थी।

लेकिन, सरकार ने इनमें से किसी भी सिफारिश को अपनाने से इनकार कर दिया और इसके लिए कोई आधिकारिक वजह भी नहीं बताई। इन सिफारिशों के हिसाब से वर्ष 2023 में राष्ट्रीय साप्ताहिक न्यूनतम वेतन 3,050 रुपए होना चाहिए।

सच्चाई

कितने मज़दूर राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन से कम कमा रहे हैं?

1/2
नियमित वेतन मज़दूर

9/10
अनियमित मज़दूर

3/5
स्वरोज़गार मज़दूर

संख्या में करीब **30 करोड़** लोग राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन से कम कमा रहे हैं यानी, उनकी कमाई गरिमा के साथ जीवन जी पाने के लिए काफी नहीं है।

यानी, जर्मनी, फ्रांस, यूके, स्पेन, नीदरलैंड, पुर्तगाल और आयरलैंड की कुल आबादी जितने लोग इन मुश्किल परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं।

सच्चाई

रेखाचित्र 4 में राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन से कम घरेलू कमाई वाले ग्रामीण और शहरी परिवारों के अनुपात (%) को दिखाया गया है। रेखाचित्र 5 में राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन से कम घरेलू कमाई वाले सिर्फ ग्रामीण परिवारों के अनुपात (%) को और रेखाचित्र 6 में सिर्फ शहरी परिवारों के अनुपात (%) को दिखाया गया है।

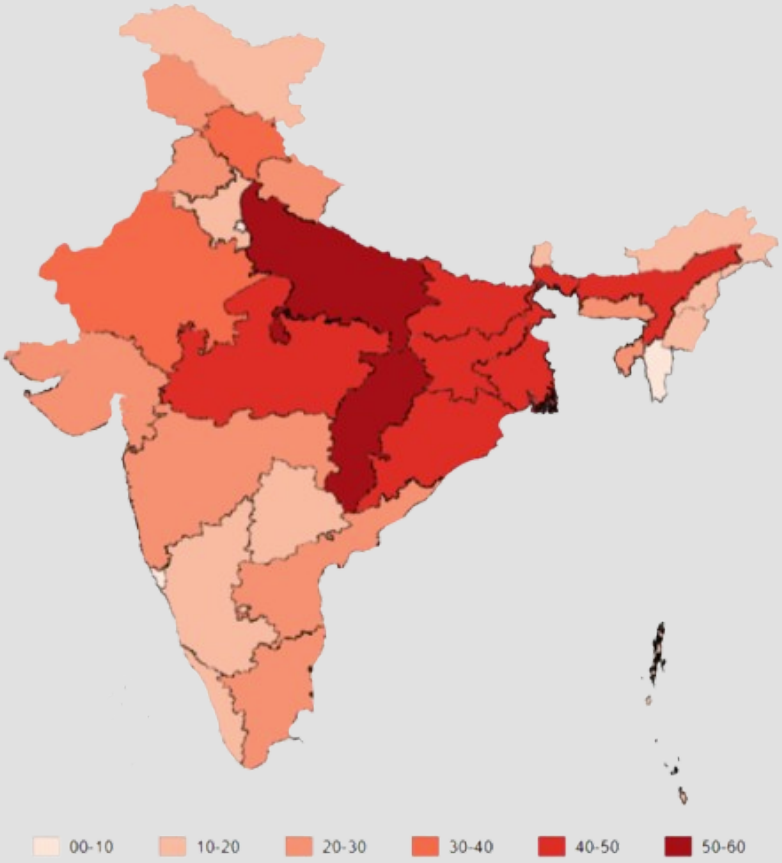

रेखाचित्र 4: राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन से कम घरेलू कमाई वाले परिवारों का अनुपात (%) - कुल (ग्रामीण+शहरी)

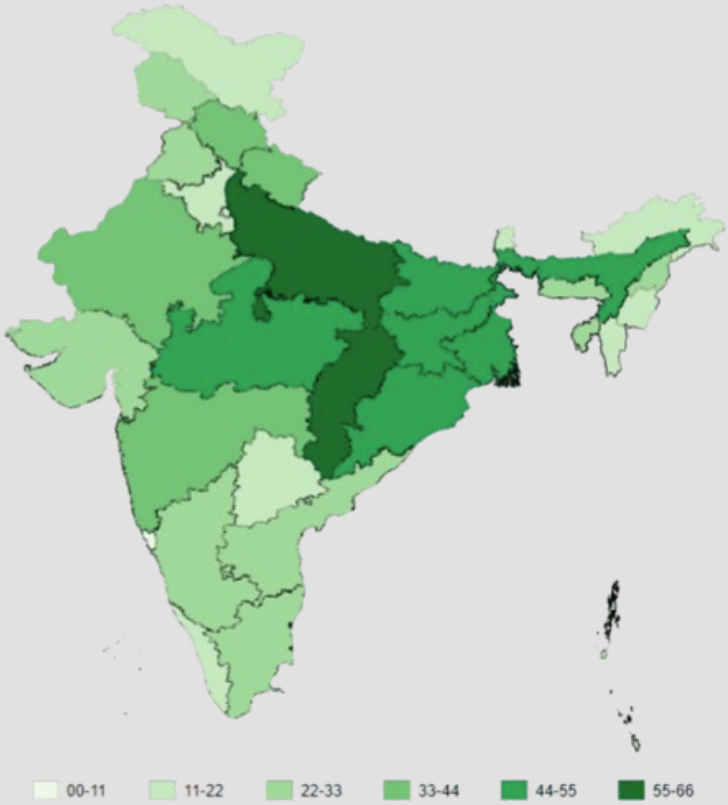

रेखाचित्र 5: राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन से कम घरेलू कमाई वाले परिवारों का अनुपात (%) - ग्रामीण

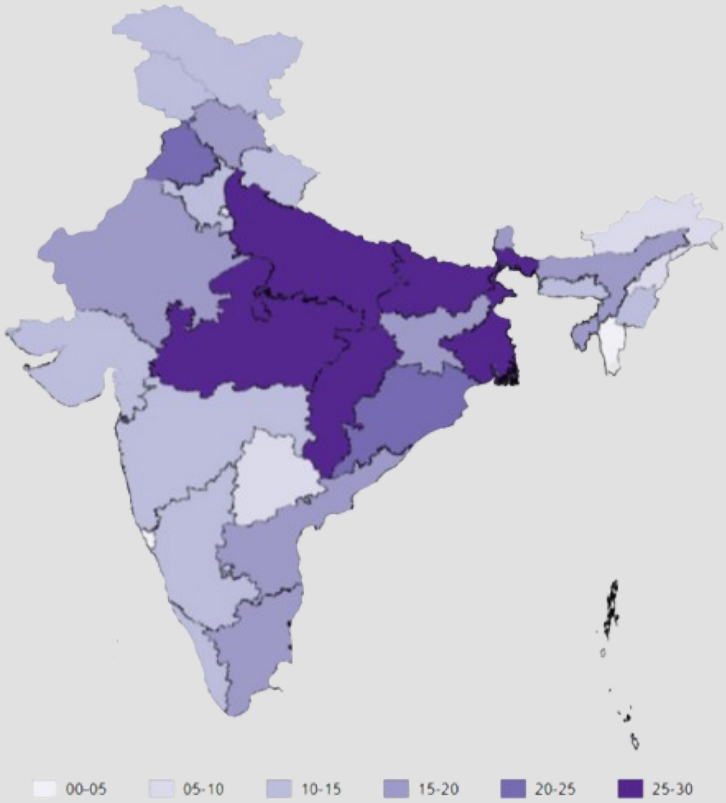

रेखाचित्र 6: राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन से कम घरेलू कमाई वाले परिवारों का अनुपात (%) - शहरी

दावे

“हमारे लिए विकास का अर्थ है गरीब से भी गरीब का विकास, दलित का, आदिवासी का, पिछड़ों का और वंचितों का विकास।”

प्रधानमंत्री मोदी, मार्च 2024

सच्चाई

वर्ष 2011-12 और 2022-23 के बीच प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी/GDP) में

60%

से अधिक की वृद्धि हुई है

जबकि गरीब तबके की आमदनी में न के बराबर बढ़ोत्तरी हुई है।

34%

परिवार राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन से भी कम कमाते हैं।

इसका मतलब है कि जीडीपी (GDP) में देखी गई वृद्धि का फायदा सिर्फ अमीरों को हुआ है।

क्या सबूत है कि जीडीपी (GDP) में हुई वृद्धि का फायदा सिर्फ अमीरों को हुआ है?*

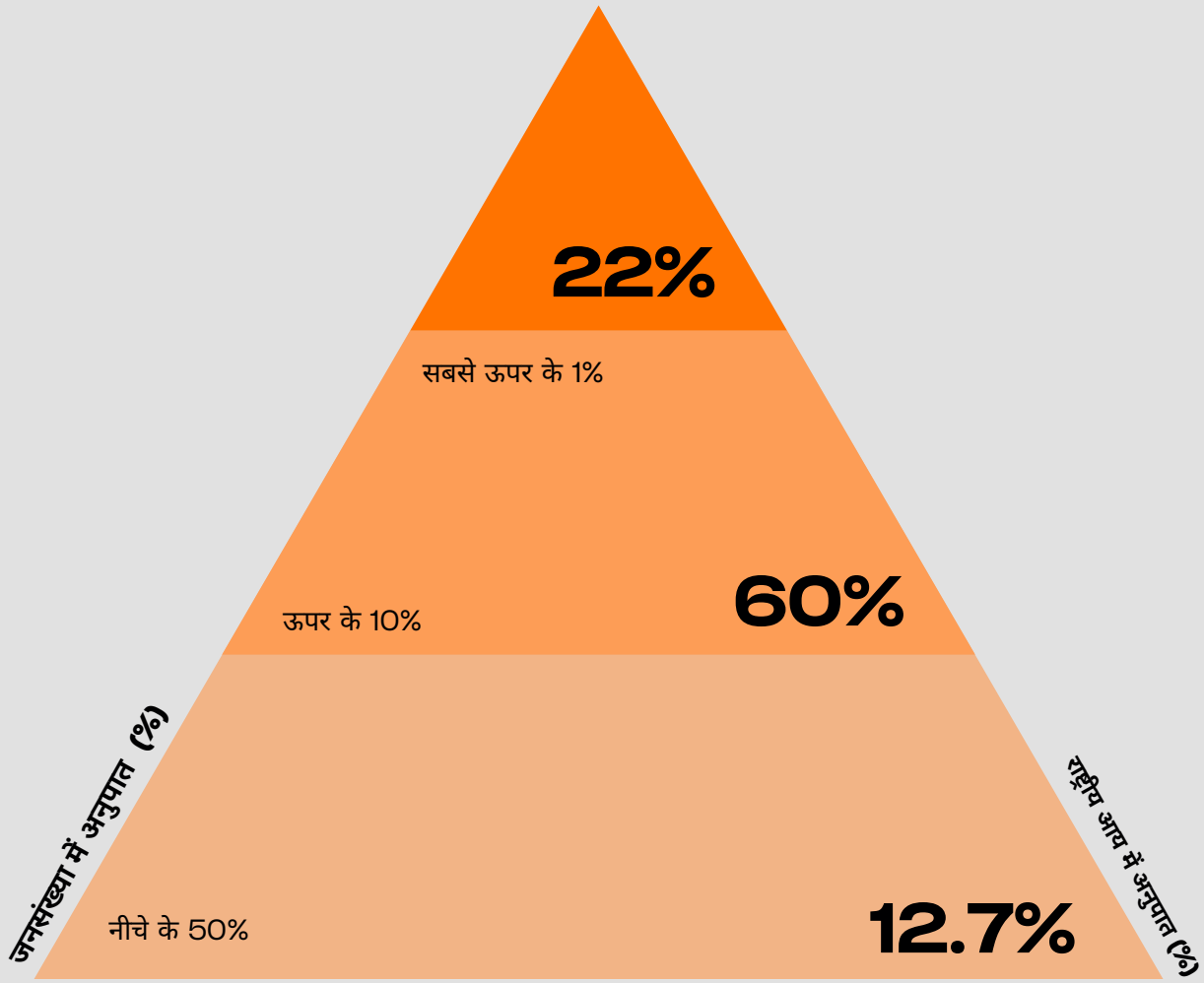

*स्रोत: https://wid.world/country/india/

सच्चाई

आमदनी की गैर-बराबरी के साथ अगर संपत्ति की गैर-बराबरी को भी देखा जाए तो अमीर और गरीब के बीच की खाई और भी गहरी है। आमदनी संपत्ति का सिर्फ एक हिस्सा है। किस व्यक्ति की संपत्ति सभी स्रोतों से होने वाली कमाई से बनती है जिसमें वेतन/आमदनी, किराया, निवेश किए गए पैसे, स्टॉक और ज़मीन, घर, कार इत्यादि से मिलने वाला ब्याज भी शामिल होता है।

रेखाचित्र 7 में ऊपर की 10% आबादी और नीचे की 50% आबादी का देश की कुल संपत्ति में अनुपात दिखाया गया है।

- वर्ष 2012 में, **राष्ट्रीय संपत्ति का 63% हिस्सा ऊपर की 10% आबादी के हाथों में था**। वर्ष 2022 में यह बढ़ कर 64.5% हो गया है।
- वर्ष 2012 में, **राष्ट्रीय संपत्ति का 6.1% हिस्सा नीचे की 50% आबादी के हाथों में था**। वर्ष 2022 में यह और घट कर सिर्फ 5.6% रह गया है।

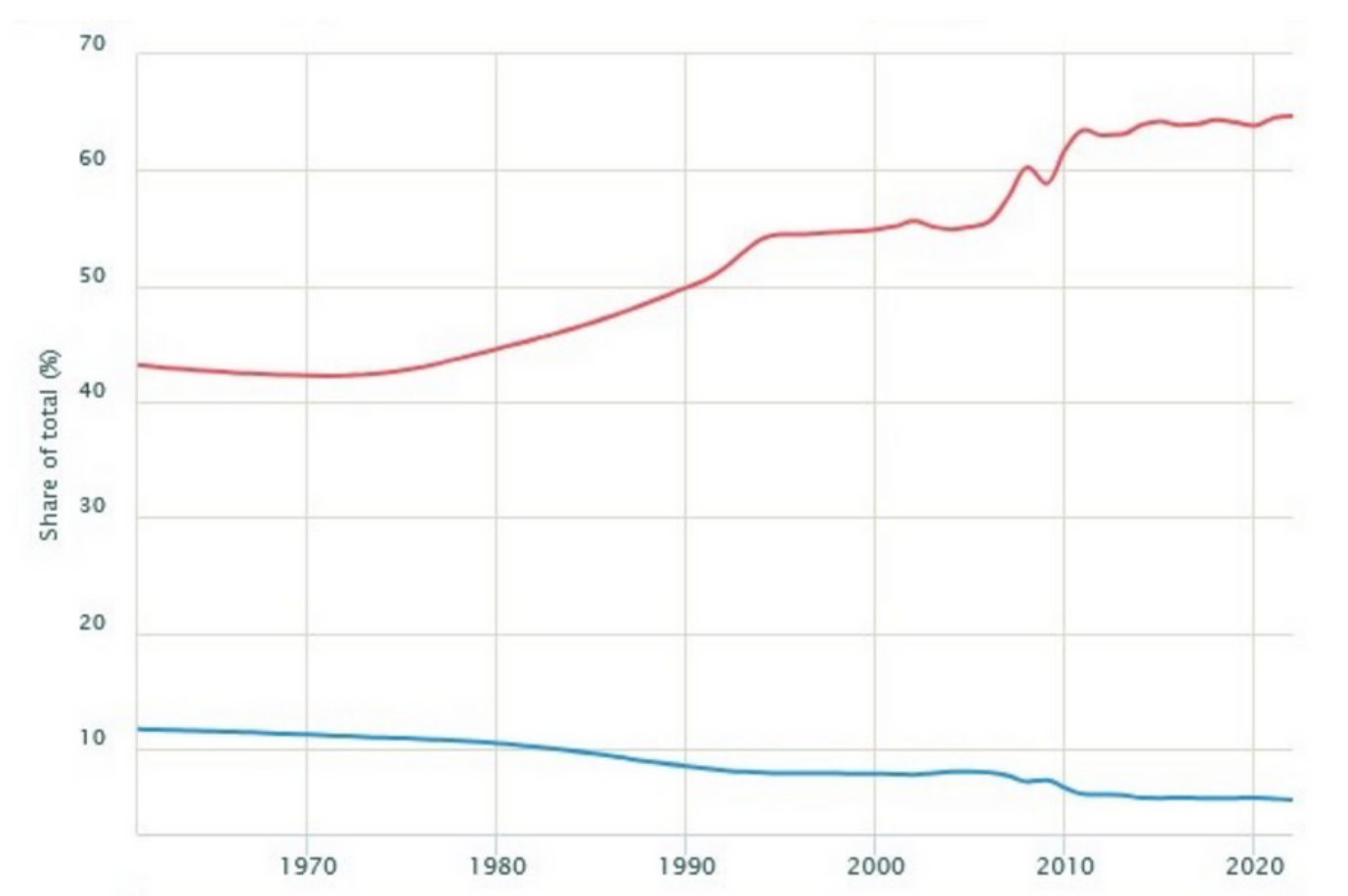

रेखाचित्र 7: ऊपर की 10% आबादी और नीचे की 50% आबादी का भारत की कुल संपत्ति में अनुपात

इस बढ़ती गैर-बराबरी का असर किस पर पड़ता है?

आमदनी और संपत्ति में मौजूद इस गैर-बराबरी का ख़मयाज़ा हाशिए के समुदायों को उठाना पड़ता है। गैर-बराबरी जैसे-जैसे बढ़ती है, सामाजिक सुरक्षा से वंचित समूह आर्थिक तौर पर और ज़्यादा असुरक्षित होते चले जाते हैं। कोविड महामारी के दौरान हमने देखा कि इस तरह के संकट के समय आर्थिक रूप से कमज़ोर और असुरक्षित तबकों का क्या हाल होता है।

हम इसके बारे में क्या कर सकता है?

एक भूखा या बीमार या पर्याप्त शिक्षा से वंचित व्यक्ति अपने आर्थिक सामर्थ्य को पूरा नहीं कर सकता है। दस साल से एक ही स्तर पर बनी हुई वेतन दर और आसमान छूती गैर-बराबरी न सिर्फ नैतिक और संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है, बल्कि यह आर्थिक विकास के लिए भी खराब है।

पर्याप्त पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा न सिर्फ समाज की खुशहाली के लिए ही बल्कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी बुनियादी शर्त है। कई जन अभियानों ने इन सभी अधिकारों को अनिवार्य, न्यायसंगत सामाजिक-आर्थिक अधिकार घोषित किया है:

इसके लिए सामाजिक सुरक्षा बजट के लिए जीडीपी (GDP) के

10%

के आवंटन की ज़रूरत होगी। मौजूदा स्रोतों के अलावा, इनके लिए बजट जुटाने के लिए आबादी के सबसे ऊपर के 1% हिस्से पर

2%

संपत्ति कर और

33.3%

उत्तराधिकार कर भी लगाया जा सकता है।

सभी के लिए पोषण का अधिकार
सभी के लिए रोज़गार का अधिकार जिसके जीवन-निर्वाह वेतन मिले और इसका समय पर भुगतान हो
मुफ्त और अच्छी चिकित्सा का अधिकार
मुफ्त और अच्छी शिक्षा का अधिकार
पेंशन का अधिकार

* देखें, निखिल डे, अरुणा रॉय और रक्षिता स्वामी द्वारा सम्पादित, 'वी दा पीपल: एस्टेब्लिशिंग राइट्स एंड डिपनिंग डेमोक्रेसी' का प्रभात पटनायक और जयति घोष द्वारा लिखित पहला अध्याय जिसमें कुछ सार्वभौमिक आर्थिक अधिकारों का ज़िक्र किया गया है।

सच्चाई

वर्ष 2024 के केंद्रीय बजट में भाजपा की प्राथमिकता क्या है?

रेखाचित्र 8 दिखाता है कि 5 सामाजिक क्षेत्र योजनाओं पर किया गया कुल खर्च जीडीपी (GDP) का सिर्फ 0.40% हैं।*

रेखाचित्र 8: पांच सामाजिक योजनाओं के लिए आवंटित बजट, जीडीपी (GDP) के अनुपात (%) के रूप में

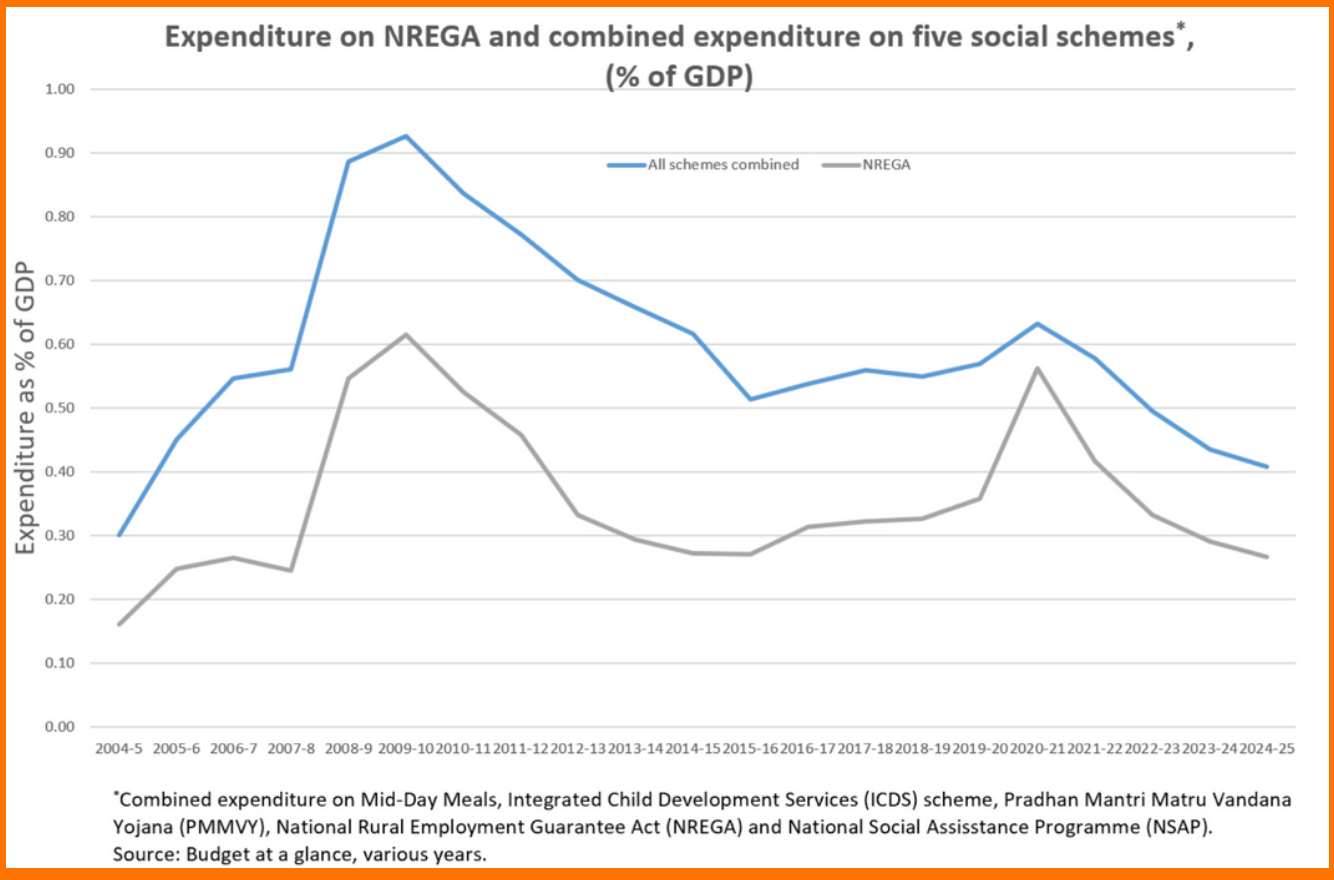

*स्रोत: https://twitter.com/roadscholarz/status/1753006844497334626/photo/1

रोज़गार, वेतन और गैर-बराबरी

ईमेल bahutvakarnataka@gmail.com
फेसबुक Bahutva Karnataka
इंस्टाग्राम @bahutvakarnataka
ट्विटर @BahutvaKtka